

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ.53(01)/अता0 प्र0.130/चतुर्थ सत्र(चतुर्थ भाग-2023)/दिविस/श.वि./ 6286

दिनांक: 27.11.2024

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय: सातवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र (चतुर्थ भाग) 2023 अतारांकित प्र0 सं0.130 माननीय विधायक
श्री राजेश गुप्ता दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की प्रतियाँ माननीय मंत्री शहरी विकास
विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री राजेश गुप्ता

दिनांक : 18.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 130

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एम.सी.डी. की लाइटस लगभग 08 वर्षों से बन्द पड़ी हैं जिसका पैसा एमसीडी नहीं भर रही थी।	<p>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:- वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की लाइटें 08 वर्षों से बन्द नहीं हैं। दिल्ली नगर निगम इन लाइटों के बिजली बिल का भुगतान अक्टूबर 2019 तक करता रहा था इसके उपरान्त डीएसआईआईडीसी के द्वारा टीपीडीडीएल को इन बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण इन लाइटों की विद्युत सप्लाई जनवरी 2021 में बन्द कर दी थी। अतः उपरोक्त लाइटें जनवरी 2021 तक चालू थी।</p> <p>ज्ञातव्य है कि राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 08-06-2010 (अनुलग्नक 'क') एवं उद्योग विभाग की राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 11-11-2011 (अनुलग्नक 'ख') के द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार सभी औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा और फ्लैट फैक्ट्री परिसर का संचालन और रखरखाव और प्रबंधन तथा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं डीएसआईआईडीसी द्वारा किया जाना तय किया गया था।</p> <p>उक्त अधिसूचना के अनुपालन में दिल्ली नगर निगम वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की लाइटों को डीएसआईआईडीसी को हस्तांतरित करने हेतु प्रयासरत है। इस सन्दर्भ में दिल्ली नगर निगम द्वारा डीएसआईआईडीसी के साथ किये गये पत्र व्यवहार दिनांक 27-01-2022, 20-12-2022, 23-01-2023 तथा 20-12-2023 की प्रतिलिपियां (अनुलग्नक ग-1,2,3, एवं 4) पर संलग्न है, किन्तु डीएसआईआईडीसी ने उक्त अधिसूचना का अनुपालन अभी तक नहीं किया है तथा वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल ऐरिया में लगी स्ट्रीट लाइटस तथा हाई मास्ट लाइटों की मैन्टेनेंस तथा इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्र की डिस्कॉम (टी.पी.डी.डी.एल) को नहीं किया था जिस वजह से टीपीडीडीएल ने इन लाइटों की विद्युत सप्लाई तथा मैन्टेनेंस बन्द कर दी। परिणामतः इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें जनवरी 2021 में बंद हो गई थी।</p> <p>वर्तमान में आम जनता की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए, खराब पड़ी हुई 20 नम्बर सेमी हाई मास्ट लाइट पोल्स को ठीक करवा दिया गया है। तथा स्ट्रीट लाइटों के विद्युत बिल का बकाया राशि रुपये 38,02,423/- का भुगतान दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा चुका है, वर्तमान में कोई भी बकाया राशि शेष नहीं है तथा माहवार विद्युत बिलों का भुगतान अनवरत रूप से किया जा रहा है, जोकि माह जुलाई, 2024 तक का भुगतान किया जा चुका है।</p>

		यद्यपि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की लाइटों के रख-रखाव तथा बिजली बिल के भुगतान की जिम्मेवारी डीएसआईआईडीसी की है। अतः इनको हस्तांतरित करने का प्रयास अनवरत जारी है।
ख	यदि हां, तो इसका पैसा सरकार देगी या फिर विधायक फंड से लिया जा सकता है, जानकारी उपलब्ध करवाये,	दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:- अधिसूचित अधिनियम के तहत, डीएसआईआईडीसी को वजीरपुर तथा अन्य इन्डस्ट्रीयल ऐरिया में लगी स्ट्रीट लाइट्स तथा हाई मास्ट लाइटों का मैन्टेनेंस तथा इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
ग	जे.जे. कॉलोनी में टीपीडीडीएल लाइट्स यह कह कर चालू नहीं कर रही है कि बेड स्विच है तो यह लाइट्स कैसे सही होगी, जानकारी उपलब्ध करवायें,	<p><u>Department of Power/Tata Power DDL</u></p> <p>In this regard we would like to inform you that the electricity network in the subject area is currently being running on HVDS (High Voltage Distribution System) network. An option and feasibility was explored for installation of new street lights on the existing HVDS but same cannot be done due to safety and technical feasibility.</p> <p>We would also like to draw to your kind attention that a joint site visit has already been conducted at K, A and L Block Wazirpur J.J. Colony on 07-08-2024 to explore the feasibility of conversion from HVDS network to LVDS network. During the visit it has been observed that shifting/conversion of existing network is technically feasible subject to availability of suitable space for installation of transformers and other electric equipments with written consent from respective LOA i.e. DUSIB. Tentative cost for this conversion work in above said three blocks only will be approx 2 crore and final estimate is subject to ETC approval. Matter has already been communicated to Hon'ble MLA vide our letter no. TPDDL/ga/2024/226 DATED 13.08.2024. Copy of the said letter is enclosed and marked as Annexure-A.</p> <p>Matter was also discussed during meeting convened by Hon'ble Minister of Power wherein all situation has been explained to Hon'ble Minister and also communicated vide our letter no. TPDDL/GA/2024/238. Copy of the same is enclosed and marked as Annexure-B</p>
घ	माननीय मुख्यमंत्री जी के निगम में आम आदमी की सरकार के बिजली का बिल भरने के आदेश के बाद इन लाइट्स की क्या स्थिति है, और	घ एवं ड दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:- वर्तमान में आम जनता की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल ऐरिया की खराब पड़ी हुई 20 नम्बर सेमी हाई मास्ट लाइट पोल को ठीक करवा दिया गया है तथा लाइटों के विद्युत बिल का भुगतान दिल्ली नगर निगम के विद्युत विभाग (केशवपुरम क्षेत्र) द्वारा किया जा रहा है
ड	क्या सारी लाइट्स चालू हो गई है ?	

1541
डि. डी. डी. - 3302/9

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D1 - 3302/9

अनुलग्नक - 'क'

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

अधिश्रुत

EXTRAORDINARY

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 90]

दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2010/शुक्ल 18, 1932

[सं. 60]

No. 90]

DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2010/JYASTHA 18, 1932

[NCTD No. 60]

भाग - IV

PART - IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No. F. 14(3)/LA-2009/EC-Law/212. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 11th May, 2010 and is hereby published for general information—

The Delhi Industrial Development Operation and Maintenance Act, 2010

(Delhi Act 68 of 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 30th March 2010)

[13th May 2010]

An Act to make special provision for securing the orderly establishment of industrial area, industrial estates and related factories complex in the National Capital Territory of Delhi, and to assist generally in the organisation, including operation and maintenance thereof, and for the purpose to reconstitute and empower Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and for purposes connected therewith or incidental thereto.

Enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Eleventh Year of the Republic of India as follows—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "apexity" includes roads, supply of water and electricity, street lighting, drainage, sewerage, green cover including plantation of trees and development of parks, conservancy and such other convenience as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be an amenity for the purpose of this Act;

(b) "approved" means approved by the authority having jurisdiction;

(c) "Building" means any structure for whatsoever purpose and of whatever materials constructed and every part thereof whether use is as human habitation or not and includes foundation, pillars, walls, floors, roofs, chimneys, plumbing and building services, fixed platform, verandah, balcony, verandah or projection, part of a building or anything affixed thereto, or any wall enclosing or intended to enclose

any land or space and signs and outdoor display structure, tents, shanties, tarpaulin shelter etc. erected for temporary and experimental measures with the permission of the Authority, shall not be considered as building.

(d) "Collector" means the Deputy Commissioner of a revenue area of Delhi, and includes any officer specially appointed by the Government to perform the functions of a Collector under this Act;

(e) "Corporation" means the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd., a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(f) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi.

(g) "development" with its grammatical variations means the carrying out, of building, engineering, quarrying or other operations in or over or under land, or the making of any material change in any building or land and includes redevelopment, but does not include mining operations, and "to develop" shall be construed accordingly;

(h) "engineering operations" include the formation or laying out of means of access to a road or the laying out of means of water supply, drainage and sewerage, construction, operation and maintenance of common Effluent Treatment Plants, laying out of means of supply of electricity, supply of drinking water, plantation of trees and development of parks, conservancy and such other operations as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be an engineering operation for the purpose of this Act;

(i) "United factories complex" means any site selected and notified by the Government, where the Corporation builds United factories and other buildings and makes them available for any industries or class of industries or existing United factories complex included in Part II of the Schedule;

(j) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated by such title as Article 239AA of the Constitution;

(k) "Industrial area" means any area declared to be an industrial area by the Government by notification in the Official Gazette, whether already developed or to be developed for the purpose of accommodating industrial unit;

(l) "Industrial building" includes any building or part of a building or structure, in which products or materials of all kinds and properties are fabricated, assembled or processed, retrieved, made, stored, factories, etc.;

(m) "Industrial estate" means any site selected and notified by the Government, where the Corporation builds factories and other buildings and makes them available for

any industries, or class of industries or any existing industrial site or area included in Part A of the Schedule;

(n) "land" the expression land shall have the meaning respectively assigned to it in Section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894);

(o) "Lieutenant Governor" means the Administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(p) "means of access" includes a road or any means of access, whether private or public, for vehicles or for foot passengers; every building/plot shall abut on a public/private means of access like streets/roads duly formed;

(q) "person interested" shall have the meaning assigned to it in Section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894);

(r) "premises" means any land or building or part of a building and includes

(i) the garden, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building; and

(ii) any fitting affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;

(s) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(t) "regulations" means regulations made by the Corporation under this Act;

(u) "Schedule" means the Schedule appended to this Act.

CHAPTER II

EMPOWERMENT OF THE CORPORATION AND ITS FUNCTIONS UNDER THIS ACT

3. **Empowerment.**—For the purpose of securing and assisting in the rapid and orderly establishment and organisation of industries in industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes and for operation and maintenance of industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes in Delhi, the Corporation shall, after the commencement of this Act, be empowered by the Government by notification in the Official Gazette and by such amendments to the Memorandum of Association of the Corporation as may be necessary.

4. **Functions.**—The functions of the Corporation shall be—

(i) generally to promote and assist in the rapid and orderly establishment, growth and development of industries in Delhi; and

(ii) in particular, and without prejudice to the generality of clause (i), to—

(a) establish, operate, maintain and manage

industrial estates at place selected and notified by the Government including the existing industrial areas, industrial estates and flatted factory complexes being maintained by the Municipal Corporation of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957). All industrial estates areas of Delhi will stand transferred to the Corporation for this purpose within prescribed time frame;

(b) develop industrial areas selected and notified by the Government for the purpose and make them available for undertakings to establish themselves;

(c) build, flatted factories complexes at sites selected and notified by the Government for the purpose and make them available for any industries and class of industries;

(d) redevelopment of clusters of industrial concentration in non-conforming areas identified and notified for redevelopment by the Government;

(e) undertake schemes of works, either jointly with other corporate bodies or institutions, or with Government or local authorities, or on an agency basis, in furtherance of the purposes for which the Corporation is established and all matters connected therewith;

(f) all functions listed in the objects clause of the Memorandum of Association of the Corporation;

(g) any other function as the Government may, by notification in the Official Gazette and by such amendments to the Memorandum of Association of the Corporation as may be necessary, prescribe for the purposes of this Act;

(h) the Corporation shall make such amendments to the Memorandum of Association as may be necessary to incorporate the functions under this section which are not part of the Memorandum of Association.

5. **General Powers of the Corporation.**—Subject to the provisions of this Act, the Corporation shall have power—

(a) to acquire and hold such property, both movable and immovable as the Corporation may deem necessary for the performance of any of its functions under section 4 and to lease, sell, exchange or otherwise transfer any property held by it on such conditions as may be prescribed by the Government;

- (b) to provide or cause to be provided amenities and common facilities in industrial estates, industrial areas and allied factories complexes and construct and maintain or cause to be maintained works and buildings therefor;
- (c) to construct buildings for the housing of the employees of such industries;
- (d) to allot factory sheds, industrial plots or such buildings or parts of buildings, including residential tenements to suitable persons in the industrial areas, estates and allied factories complexes established or developed by the Corporation in terms of the allotment policy prescribed by the Government;
- (e) to modify or rescind such allotments as provided in clause (d) above including the right and power to evict the allottees concerned on breach of any of the terms or conditions of their allotment in terms of the policy guidelines prescribed by the Government;
- (f) to constitute advisory committee to advise the Corporation;
- (g) to engage suitable consultants or persons having special knowledge or skill to assist the Corporation in the performance of its functions;
- (h) subject to the previous permission of the Government to delegate any of its powers generally or specially to any of its committee or officers and to permit them to redelegate specific powers to their subordinates;
- (i) to enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying out any of its functions;
- (j) to recover development charges from the individual industries and beneficiaries located in the clusters of industrial concentration for which redevelopment is undertaken by the Corporation;
- (k) to do such other things and perform such acts as it may think necessary or expedient for the proper conduct of its functions and for carrying into effect the purposes of this Act.

6. Power to levy service charges.—Notwithstanding anything contained in any contract or any law for the time being in force, it shall be lawful for the Corporation to levy fees or service charges in respect

of expenses on maintenance of roads, drainage, water supply, electricity, operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and such other services and amenities as may be provided by it, including provision of street lighting, at such rates as may be prescribed by the Government from time to time. Such fees or charges may be levied on the plot holders or other persons receiving benefit of the services or amenities.

- 7. Directions by the Government.—The Government may issue to the Corporation such general or special directions as to policy as it may think necessary or expedient for the purpose of carrying out the purposes of this Act, and the Corporation shall be bound to follow and act upon such directions.

CHAPTER-III

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

- 8. Creation of Industrial Development, Operation and Maintenance Fund.—(1) The Corporation shall have and maintain a fund known as the "Industrial Development, Operation and Maintenance Fund" (hereinafter referred to as "Fund") for the discharge of its functions under this Act, to which shall be credited—

- (a) all monies received by the Corporation from the Government by way of grants, subventions, loans, advances or otherwise;
- (b) all fees, costs and charges received by the Corporation under this Act;
- (c) ground rent collected with effect from the date on which this Act comes into effect from industrial plots and sheds by the Delhi Development Authority constituted under the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Corporation and the Industries Department of the Government;
- (d) all monies received by the Corporation from the disposal of lands, buildings and other properties movable and immovable, as may be prescribed;
- (e) all monies received by the Corporation by way of rents and profits or in any other manner, or from any other sources, may be prescribed.

(2) All monies received with effect from the date on which this Act comes into effect from conversion of industrial plots and sheds from leasehold to freehold by the Industries Department of the Government, Delhi Development Authority constituted under the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and the Corporation.

9. **Application of the Fund.**—The Corporation shall have the authority to spend such sums from the Fund for the purposes as may be prescribed.
10. **Grants, subventions, loans and advances to the Corporation.**—The Government may, after due appropriation made by the Legislative Assembly of Delhi by law in this behalf, make such grants, subventions, loans and advances to the Corporation as it may deem necessary for the performance of the functions of the Corporation under this Act, and all grants, subventions, loans and advances made shall be on such terms and conditions as the Government may, after consulting the Corporation, determine.
11. **Budget and Programme of work.**—(1) The Corporation shall, by such date in each year as may be prescribed, prepare and submit to the Government for approval an annual financial statement and the programme of work including operation and maintenance of industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes for the succeeding financial year.
- (2) The annual financial statement shall show the estimated receipts and expenditure during the succeeding financial year in such form and detail as may be prescribed.
- (3) The Corporation shall be empowered to make variations in the programme of work in the course of the year provided that all such variations and reappropriations out of the sanctioned budget are brought to the notice of the Government by a supplementary financial statement.
12. **Accounts and audit.**—(1) The Corporation shall maintain separate bank account and books of account and other books in respect of the Fund in relation to its business and transactions in such form and in such manner as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Corporation maintained under this Act shall be audited by the auditor appointed in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 19 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971) or by any other auditor appointed by the Government.
- (3) As soon as the accounts of the Corporation are audited, the Corporation shall send a copy thereof together with the copy of the report of the auditor thereon to the Government for laying it in the Legislative Assembly of Delhi.
13. **Concurrent and special audit of accounts.**—(1) Notwithstanding anything contained in the last preceding section, the Government may order that there shall be concurrent audit of the accounts of

the Corporation by such person as it thinks fit. The Government may also direct a special audit to be made by such person as it thinks fit of the accounts of the Corporation relating to any particular transaction or class or series of transactions or to a particular period.

(2) When an order is made under sub-section (1), the Corporation shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person appointed under sub-section (1) such information as the said person may require for the purpose of audit.

CHAPTER-IV

APPLICATION OF THE PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1971 TO CORPORATION PREMISES

14. **Application of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 to Corporation Premises.**—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, provide from such date as is stated therein that the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 (49 of 1971) shall apply to premises belonging to, vesting in, or leased by, the Corporation as that Act applies in relation to Government premises, but subject to the provisions of sub-section (2).
- (2) On a notification being issued under sub-section (1), the aforesaid Act and the rules made thereunder shall apply to premises of the Corporation with the following modifications, that is to say:
- (a) the Government shall appoint an officer who is holding or has held office whether under the Government or the Corporation, which in the opinion of the Government is not lower in rank than that of a Sub-Divisional Magistrate or an Executive Engineer, to be the competent authority for the purposes of the aforesaid Act and one or more officers may be appointed as competent authorities for different areas or for the same area;
- (b) references to "public premises" in that Act and the rules shall be deemed to be references to premises of the Corporation.

CHAPTER-V

UNUTILISED SURPLUS LANDS IN INDUSTRIAL AREAS

15. **Acquisition of unutilised surplus lands in industrial areas and allotment to other industries.**—(1) With a view to ascertaining whether any industrial area, industrial estate or flatted factories complex developed by the

Established originally or by any Government agency in the past or now conforming clusters having industrial concentration justified by the Government for redevelopment has been fully utilized for industrial purposes or not, the Government may direct the Corporation to submit to it a six monthly report containing the following information in respect of such area, namely:

- (i) the total number of plots or flats and the area of each plot or flat in the industrial area, industrial estate or flatland factory complex, as the case may be;
- (ii) the number of plots or flats allotted to the plot or flat holder and the number of plots or flats, as the case may be, still in the possession of the Corporation;
- (iii) the date on which possession of each plot or flat was delivered to the plot or flat holder, the period for which the plot or flat was allotted and the particulars of the rights or interests in the plot or flat holder;
- (iv) organized in the vicinity of each plot, having due regard to the building regulation of the Corporation or the local authority concerned within whose jurisdiction the industrial area or industrial estate is situated;
- (v) how much utilized area of each plot is expendable in sub-division and whether the utilized area can be utilized for accommodating another industry, other sub-division;
- (vi) the period for which the area of any plot (whether whole or part) remained unutilized from the date of delivery of possession to the plot holder and the reasons therefor as stated by the plot holder.

On receipt of such direction, the Corporation shall issue notices to the plot holder, to the industrial area or industrial estate calling upon them to furnish to it the information in the prescribed form and when so called upon such plot holder shall be bound to furnish the said information required within one month from the date of receipt of such notice by him/her.

For the purpose of enabling the Corporation to determine whether there is any unutilized portion of any plot in the industrial area or estate and whether such portion is capable of sub-division so as to make it useful for accommodating any other industry after sub-division it shall be lawful for a member of the Corporation, either directly or specially authorized by it in the behalf and for his servants and workmen, at all reasonable hours

- (a) to enter upon and survey the plot;
- (b) to set out the boundaries of the unutilized portion of the plot; and
- (c) to do all other acts necessary for the purposes aforesaid.

(4) If upon the report submitted by the Corporation, the Government is satisfied that any plot holder has not utilized the maximum boundary area of the plot for a period of seven years or the period fixed by the Government from time to time from the date on which possession of the plot was delivered to him by the Corporation and the unutilized portion is capable of being utilized so as to make it useful for accommodating any other industry, the Government may, notwithstanding anything contained in any contract or in any law for the time being in force before the expiry of each period from the date of receipt of such report, as may be prescribed, issue to the plot holder and all other persons interested in the plot notices to show cause why such unutilized portion should not be reserved for the purpose of being utilized for accommodating another industry. The Government shall also cause public notice to be given in the manner laid down in Section 24.

When any such notice is issued, the Government shall give a reasonable opportunity of being heard to the plot holder and other persons interested in the plot and it shall be open to the plot holder or any other persons interested in the plot to appear and object to such acquisition on the ground that the unutilized portion is needed by the plot holder himself for the purpose of immediate expansion of his own industry and that he has already taken effective steps for utilizing such portion.

Explanation.—For the purposes of this subsection, the expression "effective steps" shall mean the following steps, namely:

- (a) the plot holder has prepared the necessary project report in respect of the proposed expansion of his industry indicating the requirements of such expansion; and
- (b) (i) the plot holder has obtained, whenever necessary, letter of intent or industrial licence; (ii) has got a memorandum of Industrial Entrepreneurial Memorandum from the Government of India as required under the Industrial Development and Regulations Act, 1951 (XXV) or 1951 (XXVI); (iii) the plot holder has concluded the negotiation with financial institutions for raising the required funds; and (iv) has

per cent or more of the capital requirements for such expansion have been subscribed in the case of the company which has to go in for public issue where applicable; or

(c) the plot holder has placed a firm order for purchase of at least fifty per cent of the plant and machinery required for the purpose of expansion.

(6) If after giving a reasonable opportunity of being heard, the Government is satisfied that the holder of the plot has failed to utilize or is not likely to utilize the unutilized portion for industrial purposes within a reasonable period, and such unutilized portion can be used for accommodating another industry, Government may, notwithstanding anything contained in any contract or in any law for the time being in force for the purpose of enabling the Corporation to properly discharge its functions of promoting rapid growth and development of industries by accommodating another industry on such unutilized portion, acquire the land of such portion by publishing in the Official Gazette, a notice specifying the purpose for which the land is required, and stating therein, that the Government had decided to acquire the land in pursuance of this section. When such a notice is published in the Official Gazette, the land shall, on and from the date of such publication, vest absolutely in the Government, free from all encumbrances.

(7) Where any land is vested in the Government under the last preceding sub-section, the Government may, by notice in writing, order any person who may be in possession of the land to surrender or deliver possession thereof to the Government or any person duly authorized by it in this behalf within thirty days of the service of the notice.

(8) If any person refuses or fails to comply with an order made under the last preceding sub-section, the Government may take possession of the land, and may for that purpose use such force as may be necessary.

(9) Where any land is acquired by the Government under this section, the Government shall pay for such acquisition an amount, which shall as far as possible, be determined in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894).

Provided that the amount to be awarded and paid shall not in the case of a premium lease exceed the proportionate amount of premium paid by the plot holder or his predecessor-in-title claiming under the Corporation in respect of the land so acquired, with interest thereon at six per cent per

annum from the date of payment of the premium, and where the lease is a rental lease, the amount to be awarded shall not exceed an amount equal to five times the net average yearly proportionate rent payable by the plot holder to the Corporation in respect of the land so acquired.

CHAPTER VI

SUPPLEMENTARY AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

16. Government lands.—(1) For the furtherance of the objects of this Act, the Government may by notification published in the Official Gazette, upon such conditions as may be agreed upon between the Government and the Corporation, place at the disposal of the Corporation, any lands vested in the Government.

(2) After any such land has been developed by or under the control and supervision of the Corporation, it shall be dealt with by the Corporation in accordance with the regulations made, and directions given by the Government in this behalf.

(3) If any land placed at the disposal of the Corporation under sub-section (1) is required at any time thereafter by the Government, the Corporation shall replace it at the disposal of the Government upon such terms and conditions as may be mutually agreed upon.

17. Powers of the Corporation in case of certain defaults by owner of land in industrial area, etc.—

(1) If the Corporation after holding a local inquiry, or upon report from any of its officers or other information in its possession, is satisfied that the owner of any land in an industrial area or industrial estate has failed to provide any amenity in relation to the land which, in the opinion of the Corporation, ought to be provided or to carry out any development of the land for which permission has been obtained under this Act, the Corporation may serve upon the owner a notice requiring him to provide the amenity or carry out the development within such time as may be specified in the notice.

(2) If any such amenity is not provided or any such development is not carried out within the time specified in the notice, then, the Corporation may itself provide the amenity or carry out the development or have it provided or carried out through such agency as it deems fit.

Provided that before taking any action under this sub-section, the Corporation shall afford a reasonable opportunity to the owner of the land to show cause as to why such action should not be taken.

(3) All expenses incurred by the Corporation or the agency employed by it in providing the amenity

of carrying out the development together with interest, at such rate as the Government may by order fix, from the date when a demand for expenses is made until payment, shall be recoverable by the Corporation from the owner.

18. **Penal for construction or use of land and building contrary to terms of holding.**—(1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person undertakes or causes or construction of or alterations to any building in an industrial estate or industrial area or factory complex contrary to the terms under which he holds such building or land under this Act shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees and in the case of a continuing contravention with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who uses any land or building in an industrial estate or industrial area or factory complex contrary to the terms under which he holds such land or building under this Act or in contravention of the provisions of any regulations made in this behalf shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing contravention with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

19. **Power to lay pipe lines, etc.**—(1) (a) Within any area taken up for development under clause (b) of Section 5, the Corporation,

(ii) for the purposes of (a) carrying gas, water or electricity from a source of supply to, or (b) constructing any sewers or drains necessary for carrying off the workings and waste liquids of an industrial process through any intervening area, any person empowered in that behalf by the Government by notification in the Official Gazette (hereinafter in this section referred to as "the authorized person"), may lay down, place, maintain, alter, remove or repair any pipe lines, conduits, supply or service lines, posts or other appliances or apparatus in, on, under, over, along or across any land in such area.

(2) The Corporation or the authorized persons may at any time enter upon any land in any such area and in such event the provisions of section 20 shall mutatis mutandis apply.

(3) While exercising the powers conferred by sub-section (1), the Corporation or the authorized person shall—

- (i) where the land affected is a street, bridge, sewer, drain or tunnel, comply mutatis mutandis with the relevant provisions of the Gas Companies Act, 1863 (IV of 1863), notwithstanding the fact that the Act is not in force in the area or that the Government has not issued a notification extending such provisions to such land;
- (ii) cause as little damage as possible to the premises and the full compensation to all persons entitled for any damage sustained by them in consequence of the exercise of such power as aforesaid shall be paid, as the case may be, by the Corporation or, in the case of the authorized person, by the Government.

(4) Nothing herein shall authorize or empower the Corporation or the authorized person to lay down or place any pipe or other works into, through or against any building or in any land not dedicated to public use without the consent of the owners and occupiers thereof, except that the Corporation or that person may at any time enter upon and lay or place any new pipe in the place of an existing pipe in any land wherein any pipe has been already lawfully laid down or placed in pursuance of this Act, and may repair or alter any pipe so laid down. Provided that nothing in the aforesaid provisions shall be construed to mean that the Corporation or other person is forbidden from having the said land acquired at any time by the Government in the normal course.

(5) Nothing contained in this Act or any rule or regulation made thereunder shall have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

20. **Powers of entry.**—Any officer of the Government, any member of the Corporation, and any person either generally or specially authorized by the Corporation in that behalf, may enter into or upon any land or building with or without assistants or workmen for the purpose of—

- (a) carrying out any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry or taking levels of such land or buildings;
- (b) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;
- (c) digging or boring into the sub-soil;
- (d) setting out boundaries and intended lines of work.

- (e) marking such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches;
- (f) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act.

Provided that—

- (i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building;
- (ii) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable women (if any) to withdraw from such land or building;
- (iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

21. Officers of the Corporation may be vested with other powers.—The Government may by notification in the Official Gazette, nominate any officer of the Corporation to be a controller or licensing authority under any law for the time being in force relating to the procurement or distribution of any commodity in respect of the industrial undertakings established or to be established in the industrial estates or industrial areas or slated factories complexes entrusted to or developed by the Corporation and no such nomination shall be called into question merely on the ground that such officer is not an officer of the Government.

22. Recovery of sums due to the Corporation as arrears of land revenue.—All sums payable by any person to the Corporation or recoverable by it by or under this Act and all charges or expenses incurred in connection therewith shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable as an arrear of land revenue on the application of the Corporation.

23. Service of notices etc.—(1) All notices, orders and other documents required by this Act or any rule or regulation made thereunder to be served upon any person shall, save as otherwise provided in this Act or such rule or regulation, be deemed to be duly served—

- (a) where the person to be served is a company, the service is effected in accordance with the provisions of section 51 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (b) where the person to be served is a firm, if the document is addressed to the firm at its principal place of business, identifying it by the name or style under which its business is carried on, and is either—

(i) sent under a certificate of posting or by registered post, or

(ii) left at the said place of business;

(c) where the person to be served is a statutory public body or a corporation or a society or other body, if the document is addressed to the secretary, treasurer or other head officer of that body, corporation or society at its principal office and is either—

(i) sent under a certificate of posting or by registered post, or

(ii) left at that office;

(d) in any other case, if the document is addressed to the person to be served and—

(i) is given or tendered to him, or

(ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates; or

(iii) is sent under a certificate of posting or by registered post to that person.

(2) Any document which is required or authorized to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" or "the occupier" as the case may be of that land or building (naming that land or building) without further name or description and shall be deemed to be duly served—

(a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of subsection (1); or

(b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed, is given or tendered to some person on the land or building or, where there is no person on the land or building to whom it can be delivered, is affixed to some conspicuous part of the land or building.

(3) Where a document is served on the firm in accordance with this section, the document shall be deemed to be served on each partner.

(4) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any property, the occupier (if any) of the property may be required by notice in writing by the Government or the Corporation, as the case may be, to state the name and address of the owner thereof.

24. Public notices how to be made known.—Every public notice given under this Act or any rule or regulation made thereunder shall be in writing over

the signature of the officer concerned and shall be widely made known in the locality to be affected thereby affixing copies thereof in conspicuous public places, within the said locality, or by publishing the same by beat of drum or by advertisement in a local newspaper, or by any two or more of these means, and by any other means that the officer may think fit.

25. **Notices, etc. to fix reasonable limit.**—Where any notice, order or other document issued or made under this Act or any rule or regulation made thereunder requires anything to be done for the doing of which no time is fixed in this Act or the rule or regulation, the notice, order or other document shall specify a reasonable period of time for doing the same or complying therewith.

26. **Furnishing of returns, etc.**—(1) The Corporation shall furnish to the Government such returns, accounts, reports, accounts and other information with respect to its conduct of affairs, properties or activities or in regard to any proposed work or scheme as the Government may from time to time require.

(2) The Corporation shall in addition to the audit report referred to in Section 12 furnish to the Government an annual report on its working as soon as may be, after the end of each financial year in such form and details as may be prescribed and a copy of the annual report shall be placed before the Legislative Assembly of Delhi as soon as may be after it is received by the Government.

27. **Withdrawal of area or estate or part thereof.**—Where the Government is satisfied that in respect of any particular industrial estate or industrial area or any part thereof, the purpose for which the Corporation was empowered under this Act has been substantially achieved so as to render the continued existence of such estate or area or part thereof under the Corporation unnecessary, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare that such industrial estate or industrial area or part thereof has been removed from the jurisdiction of the Corporation. The Government may also make such other incidental arrangements for the administration of such estate or area or part thereof as the circumstances may require.

28. **Authority for prosecution.**—Unless otherwise expressly provided, no Court shall take cognizance of any offence relating to property belonging to or vested by or under this Act in the Corporation, punishable under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the Corporation or some person authorized by the Corporation by general or special order in this behalf.

29. **Compensation of offences by Corporation.**—(1) The Corporation or any person authorized by the Corporation by general or special order in this behalf may, either before or after the institution of the proceedings, compound any offence made punishable by or under this Act.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence compounded.

30. **Offences by companies.**—(1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that, nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

31. **Penalty for obstruction.**—Any person who obstructs the entry of a person authorized under Section 24 to enter into or upon any land or building or prevents such person after such entry or who obstructs the lawful exercise by him of any power conferred by or under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

32. **Power to make rules.**—(1) The Government after consultation with the Corporation in regard to matters concerning it, may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) under section 4 to entrust other functions to the Corporation;
- (b) to prescribe the conditions to lease, sell, exchange or otherwise transfer property held by the Corporation under clause (a) to prescribe allotment policy under clause (d) and to prescribe policy guidelines to effect the allottees concerned under clause (e) of section 5;
- (c) to prescribe fees and charges to be levied for providing services and amenities including street lighting services under section 6;
- (d) under section 8, components of industrial development grant and maintenance fund;
- (e) to prescribe purposes for which the grant from the Fund may be spent by the Corporation;
- (f) under section 11, the date by which the annual financial statement and programme of work shall be submitted by the Corporation to the Government and the form and manner of preparing such statement;
- (g) under section 12, the form and manner of maintaining accounts;
- (h) to prescribe the period after which notice to show cause may be issued to the plot holder to acquire unutilised portion of the plot under section 15;
- (i) under section 26, the form and the details to be given in the annual report;
- (j) of the fees which may be charged by the Corporation;
- (k) any other matter which has to be, or may be, prescribed by rules.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or three successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may

be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

13. Power to make regulations.—(1) The Corporation may, with the previous approval of the Government, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder, to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) under section 10, the form and the details to be given in the annual report in which Corporation shall be dealt with by the Corporation after development;
- (b) under section 18, the Committee of the Corporation to hear appeals under that section and the procedure to be followed by it;
- (c) under section 29, the additional terms and conditions subject to which lands and buildings in industrial estate and industrial area may be held or used;
- (d) any other matter which has to be, or may be, prescribed by regulations.

(3) Every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or three successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the regulation or the House agrees that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation.

14. Protection of action taken in good faith.—No civil prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or regulation made thereunder.

15. Members, officers and staff of Corporation to be public servants.—All members, officers and servants of the Corporation shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (42 of 1860).

36. Industrial Area Development or Redevelopment to be in conformity with the Master Plan for Delhi.—Any industrial area to be developed or redeveloped by the Corporation under the provisions of this Act shall be in conformity with the Master Plan for Delhi notified under the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

37. Power to remove doubts and difficulties.—If any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, make provisions or give such directions not inconsistent with the express provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the doubt or difficulty, and the order of the Government in such cases shall be final.

SCHEDULE I

PART (A)
LIST OF EXISTING INDUSTRIAL ESTATES AREAS

- (1) G.T. Karnal Road Industrial Area
- (2) Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area
- (3) S.M.A. Industrial Area
- (4) S.S.L. Industrial Area
- (5) Wazirpur Industrial Area
- (6) Lawrence Road Industrial Area
- (7) Udyog Nagar Industrial Area
- (8) D.S.I.D.C. Sheds Nanpuri
- (9) Mangro Park Industrial Area (BDA/DCA and DSIDC)
- (10) Badli Industrial Area
- (11) Narela Industrial Area
- (12) Rawana Industrial Area

- (13) Oldha Industrial Area, Ph-I and Ph-II (BDA/DCA and DSIDC)
- (14) Oldha Industrial Estate, Phase III
- (15) Functional Industrial Estate for Electronics, S-Block, Oldha Industrial Area
- (16) Functional Industrial Estate for Electronics, A-Block, Oldha Industrial Area
- (17) Moti Cooperative Industrial Estate
- (18) Rail Road Road Industrial Area
- (19) Shalimar Bagh Industrial Area
- (20) Naraina Industrial Area, Ph-I and Ph-II
- (21) Mayapuri Industrial Area, Ph-I and Ph-II
- (22) Vasant Nagar Industrial Area
- (23) Kirti Nagar Industrial Area
- (24) D.L.F. Industrial Area, Moti Nagar
- (25) Najafgarh Road Industrial Area
- (26) Jhilmil Industrial Area
- (27) Friends Colony Industrial Area, Shalimar
- (28) Pappu Darg Industrial Area
- (29) Shalimar Industrial Area

PART (B)
LIST OF EXISTING FLATTED FACTORY COMPLEX

- (1) Flatted Factories Complex at Rail Road Road
- (2) Flatted Factories Complex, Oldha Industrial Area
- (3) Flatted Factories for Leather Goods, Wazirpur Industrial Area
- (4) Flatted Factories Complex at Jhilmil Industrial Area

SAVITARAO, J. Secy

31/08/2011 142/c

**INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 11th November, 2011

No. F. Comm/CI/2007/31/(Vol. III)/5043.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 (Delhi Act, 08 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi, after consultation with Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. in regards matters concerning it, hereby makes the following rules, namely :—

The Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Rules, 2011

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,
- (a) "Act" means the Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance Act, 2010 (Delhi Act, 08 of 2010);
- (b) "company" means a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (c) "firm" means a firm as defined in Section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932);
- (d) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation appointed by the Government;
- (e) "notification" means a notification published in the official Gazette;
- (f) "occupier" in relation to any establishment, factory or premises, means the person who has control over the affairs of the establishment, factory or premises, as the case may be, and includes, in relation to any substance, the person in possession of the substance;
- (g) "user" means any establishment, factory or premises located within the industrial area using services such as construction or maintenance of roads, drainage, operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and such other services and amenities as may be provided by the Corporation.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

141/c

CHAPTER-II

FUNCTIONS

3. Time frame for transfer of all industrial estates/areas to the Corporation under sub-clause (a) of clause (ii) of Section 4 of the Act.—(1) All the industrial areas/estates and flatted factories complexes which are presently with the Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority and the Industries Department shall stand transferred to the Corporation with effect from the date of publication of these rules in the official Gazette for the purpose of securing and assisting in the rapid and orderly establishment and organisation of industries in industries areas/estates and flatted factories complexes and for their operation and maintenance and management under the Act.

(2) Physical handing over/taking over of the transferred industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes shall be completed within 90 days from the date of commencement of the Rules.

4. Functions to be performed by the Corporation under sub-clause (g) of clause (ii) of Section 4 of the Act.—The Government may by notification in the official Gazette, assign any other functions not specified mentioned in sub-clause (a) (h) of clause (ii) of Section 4 of the Act to the Corporation as may be necessary for the purposes of this Act.

CHAPTER-III

ALLOTMENT OF DEVELOPED PLOTS, FACTORY SHEDS, BUILDINGS OR PARTS
OF BUILDINGS, RESIDENTIAL TENEMENTS

5. Conditions to lease, sell, exchange or otherwise transfer property under Section 5(a) of the Act.—The Corporation may with the prior approval of the Government provide for terms and conditions on which to lease, sell, exchange or otherwise transfer any property held by it under different schemes and categories in the regulations framed under Section 33 of the Act.

6. Allotment of developed land under Section 5(d) of the Act.—(1) The Corporation shall with the prior approval of the Government formulate policies for allotment of developed land for public utilities, community facilities, open spaces, parks, residential purposes, industrial and commercial uses and such purposes as may be specified from time to time on such terms and conditions and at such rate and to such categories of persons as may be provided for in the allotment policy which shall be incorporated in the regulations framed under Section 33 of the Act.

(2) To formulate policies under this rule, the Corporation may consult such stakeholders as it may consider necessary.

7. Policy guidelines to evict the allottee under Section 5(e) of the Act.—(1) The Corporation may modify or rescind allotments made with the approval of the Lessor for any one or all of the following reasons :—

- (a) If it is discovered that allotment/lease has been obtained by suppression of any fact or by any mis-statement or mis-representation or fraud.
- (b) Violation of terms and conditions of allotment and/or lease agreement or both by the lessee.
- (c) Violation of any of the provisions of the Act.
- (d) The following shall not be treated as violations :—
 - (i) The allottee/occupier running industrial activity other than for which the plot is allotted but is in conformity to the Master Plan of Delhi in force.
 - (ii) The allottee/occupier running permissible commercial activity subject to obtaining approval of the Municipal Corporation of Delhi or Delhi Development Authority and/or Corporation as the case may be.
 - (iii) Premises given on rent to any other firm/company/person with the approval of the Corporation for carrying out permissible activities.

(2) It shall be lawful for the Lessor, notwithstanding the waiver of any previous cause or right of re-entry upon the industrial plot and the building thereon/shed/flatted factory hereby demised to re-enter upon and take possession of the industrial plot and the buildings and the fixtures thereon and thereupon his Lease/Allotment shall cease and determine and the lessee shall not be entitled to any compensation whatsoever nor to the return of any premium paid by the lessee.

(3) Notwithstanding anything contained to the contrary in the lease-deed and the allotment letter, the Lessor may without prejudice to his right of re-entry as aforesaid, and in his absolute discretion, waive or condone breaches, temporary or otherwise on receipt of such amount and on such terms and conditions as may be determined by him and may also accept the payment of the said sum or sums or the rent which shall be arrear together with simple interest at the rate of fifteen percent per annum or at such rate as may be fixed by the Government from time to time.

(1) No forfeiture or re-entry shall be effected until the Lessor has served on the Lessee a notice in writing—

- (a) specifying the particular breach complained of, and
- (b) if the breach is capable of remedy, requiring the Lessee to remedy the breach.

(5) All notices, orders shall be served in terms of Sections 15 and 23 of the Act.

(6) Replies to the show-cause notice shall be examined by the Corporation and if the said reply is found to be unsatisfactory the Corporation may cancel the allotment of the plot/shed /flatted factory with the approval of Lessor and issue order of determination of the lease. Reasonable opportunity of being heard shall be given to the plot/shed/flatted factory holder and the present occupant(s) on the plot/shed /flatted factory before determination of the lease. A detailed order of determination specifying therein the grounds of determination and the reasons as to why the reply from the allottee has not been found satisfactory shall be passed by the Corporation.

(7) The allottee may if he so desires file review application against the order of determination to the Lessor for restoration of lease within 30 days from the date of receipt of the determination order. In case no review application is filed within the specified period of 30 days, the Lessee will be directed to hand over peaceful possession of the plot/shed/flatted factory within 7 days from the date of issue of such directions. In the event of Lessee refusing to hand over peaceful possession of the allotted plot/shed /flatted factory, eviction proceedings may be initiated by the Corporation by filing eviction case before the Estate Officer appointed by the Government by notification in the Official Gazette, under the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971.

(8) Similarly, on rejection of review application filed by the lessee, the eviction proceedings may be initiated by the Corporation in terms of sub-rule (7) above.

(9) The lease will be restored to the absolute satisfaction of Lessor as regards removal of the breach of the terms and conditions and subject to recovery of the restoration charges as may be fixed by the Lessor from time to time.

8. Levy of fees and charges for providing services under Section 6 of the Act.—(1) The users of the services such as construction, maintenance of roads, drainage, operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and such other services and amenities as may be provided by the Corporation, shall be required to pay part of the expenditure incurred on the operation and maintenance as may be fixed by the Corporation. Each industrial area/industrial estate / flatted factories complex shall be considered as a separate cost centre for the purposes of service charges. The Corporation shall levy and collect from each user the apportioned share of fee and charges payable by him. The manner of calculation of the share of fee and charges among the users shall be in accordance with the formula given in Schedule - I.

(2) The users of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) shall have to pay proportionate share of their respective contribution worked out as per the formula given in Common Effluent Treatment Plant Act, 2000 and the Common Effluent Treatment Plant Rules, 2001 made thereunder.

(3) The users of any future Common Effluent Treatment Plant built by the Corporation in any industrial area, industrial estate, flatted factories complex or any area operated and maintained by the Corporation under the Act shall have to pay proportionate share of their respective contribution worked out as per formula given in Rule 8(2) above.

(4) Users of only those industrial areas, shall have to pay for operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plant (s) where operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plants is entrusted to the Corporation.

(5) Users of industrial areas where operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plant is with the Common Effluent Treatment Plant Society, shall continue to pay to the respective Society towards the cost of operation and maintenance of Common Effluent Treatment Plant.

(6) **The manner of collection of the share of fee and charges.—**The collection of the share of fee and charges shall be made in the following manner :—

- (i) The Corporation shall issue demand letter to the users directly and/or through any agency/association of industrial plot holders nominated by the Corporation.
- (ii) The users to whom the demand letter has been served shall deposit the dues with the Corporation and/or the agency/association of industrial plot holders nominated by the Corporation within the specified period.
- (iii) In the event of failure or refusal to pay the apportioned fee by the user, the Corporation may initiate recovery proceedings against such users for recovery of fee and charges alongwith interest at such rate as the Government may fix from time to time as arrears of land revenue under Section 22 of the Act.

139/C

9. Creation of Industrial Development, Operation and Maintenance Fund under Section 8 of the Act.—(1) The Corporation shall open and operate a separate account(s) in respect of each industrial area/flatted factories complex in any of the scheduled bank and all receipts under the 'Industrial Development, Operation and Maintenance Funds' shall be deposited in the said account(s). All expenses mentioned under rule 11 below shall be met by the Corporation from this/these account(s).

(2) The components of industrial development, operation and maintenance fund under clause (d) and (e) sub-section (1) of Section 8 of the Act shall be as under :—

- (a) all monies received by the Corporation from the rent/disposal of lands, buildings and other properties movable and immovable, transferred under the Act though shall form part of the Fund but shall be used by the Corporation for acquisition and development of industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes.
- (b) all monies received by the Corporation by way of ground rents, parking fee, entry fee of heavy vehicles in the industrial area/estate/flatted factories complex, hoardings, paid public toilets.

10. Application of Industrial Development, Operation and Maintenance Fund under Section 9 of the Act.—The Corporation shall have the authority to spend sums from the fund for the purposes

- (1) establishment, growth and development of industrial areas, industrial estates and flatted factories complexes in the National Capital Territory of Delhi under the Act;
- (2) establish, operate, maintain and manage industrial estates selected and notified by the Government under the Act including the existing industrial areas, industrial estates and flatted factory complexes in the National Capital Territory of Delhi;
- (3) for development and construction of buildings, flatted factories complexes and development of industrial plots at sites selected and notified by the Government in the National Capital Territory of Delhi under the Act for the purpose and make them available for any industries and class of industries;
- (4) to provide amenities and common facilities in industrial estates, industrial areas and flatted factory complexes and construct and maintain or cause to be maintained works and buildings therefor;
- (5) to construct buildings for the housing of the employees of industries in industrial estates, industrial areas and flatted factories complexes developed by the Corporation in the National Capital Territory of Delhi under the Act;
- (6) to make payments to the consultants, architects, or persons or contractors engaged to assist the Corporation in performance of its functions;
- (7) to make payment to agencies, or persons engaged for watch and ward and security of the assets created with the Fund under the Act;
- (8) to make payment to the employees engaged by the Corporation for carrying out development, operation and maintenance and other functions related to it under the Act;
- (9) to meet expenditure to be incurred—
 - (i) within any area taken up for development under Section 5(b) of the Act, and
 - (ii) for the purposes of— (a) carrying gas, water, electricity from a source of supply to, or (b) constructing any sewers or drains necessary for carrying off the workings and waste liquids of an industrial process;
- (10) to make payment of compensation to all persons interested as defined in the Land Acquisition Act, 1894 and entitled towards the acquisition of land acquired for development of industrial estates, industrial areas, construction and development of flatted factories under the Act;
- (11) to make payment of full compensation to all persons entitled for any damage sustained by the Corporation;
- (12) to make payment towards publication of advertisements, literature, brochures, etc. for carrying out functions of the Corporations for the purposes of the Act;
- (13) Any other expenditure incurred by the Corporation for carrying out the functions assigned to it under Sections 4 and 5 of the Act.

the plot was delivered to him by the Corporation and the unutilized portion is capable of sub-division so as to make it useful, accommodating any other industry, the Government may, notwithstanding anything contained in any contract or in any law for the time being in force before the expiry of six months from the date of receipt of such report issue to the plot holder and all other persons interested in the plot, notices to show-cause why such unutilized portion should not be acquired for the purpose of being utilized for accommodating another industry.

The following shall not be treated as unutilized portion if:

- (i) The allottee/occupier running industrial activity other than for which the plot is allotted but is in conformity to the Master Plan of Delhi in force.
- (ii) The allottee/occupier running permissible commercial activity subject to obtaining 'No Objection Certificate' from the lease management agency in terms of provisions of the lease deed and approval of the Local Body and payment of conversion charges as notified by the Ministry of Urban Development, Government of India and/or the Local Body, as the case may be, from time to time. However, commercial activity shall not be allowed on the plots allotted under the relocation scheme.
- (iii) Premises given on rent to any other firm/company/person for industrial activities or commercial activities where permission for conversion from industrial activity to commercial activity has been obtained and conversion charges have been paid in terms of (ii) above. This will be applicable only in respect of those premises which have been got converted into freehold and/or where subletting permission has been obtained from the Lessor. However, commercial activity shall not be allowed on the plots allotted under the relocation scheme.
- (iv) Where the land is being used in conformity to the Master Plan of Delhi in force.
- (v) Where building is constructed in accordance with the building bye-laws and Master Plan of Delhi in force.

CHAPTER-VI

SUPPLEMENTARY AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

15. Services of notices, etc. under section 23 of the Act.—(1) All notices, orders and other documents be deemed duly served in the manner laid down as under:—

- (a) where the person to be served is a company, the service is effected in accordance with the provisions of Section 51 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (b) where the person to be served is a firm, if the document is addressed to the firm at its principal place of business, identifying it by the name or style under which its business is carried on, and is either—
 - (i) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to any of its partners or some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or
 - (ii) is sent under a certificate of posting or by registered post;
 - (c) where the person to be served is a statutory public body or a corporation or a society or other body, if the document is addressed to the secretary, treasurer or other head officer of that body, corporation or society at its principal office and is either—
 - (i) is given or tendered to him, or
 - (ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates; or
 - (iii) is sent under a certificate of posting or by registered post;
 - (d) in any other case, if the documents is addressed to the person to be served and
 - (i) is given or tendered to him, or
 - (ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or
 - (iii) is sent under a certificate of posting or by registered post to that person.
- (2) Any document which is required or authorized to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" or "the occupier", as the case may be, of that land or building (naming that land or building) without further name or description and shall be deemed to be duly served—

CHAPTER-IV

11. Annual Financial Statement and other statements and reports to be furnished by the corporation and manner of maintaining accounts under sections 11 and 12 of the Act.

- (1) Budget and programme of work.—(1) The Corporation shall submit to the Government before the 1st day of February of each year the annual financial statement and programme of work for the succeeding financial year.
- (2) The annual financial statement and the supplementary financial statement, if any, shall be in Form 'A' and the programme of work in Form 'B' and these statements shall be uploaded on the web-site of DSIIDC.
- (3) The Corporation shall also forward to the Government with its programme of work, a note giving history and description of each scheme including *inter alia* the progress made, expenditure incurred and receipts accrued in the previous years in respect of continuing schemes.
- (4) The Corporation shall be competent to make variations in the programme of work in the course of the year.
- (5) The Corporation shall bring to the notice of the Government all such variations and re-appropriations out of the sanctioned budget by a supplementary financial statement, if any, in Form 'A' and programme of work in Form 'B'.

The note shall, in particular, bring out the Financial implication of each scheme.

12. Maintaining of accounts.—(1) For the purpose of this Act, the accounts of the Corporation shall be prepared and maintained in the system as on time being followed by the Corporation.

- (2) The annual statement of accounts to be submitted to the Government under sub-section (3) of Section 12 of the Act shall be in Form 'C'.
- (3) The Corporation shall cause separate regular accounts to be kept in respect of the Fund in relation to its business and transactions under the Act.

13. Annual report and other returns.—(1) The Corporation shall within three months of the date of closing of each financial year submit to the Government an annual report relating to account of the Corporation under the Act.

(2) The report shall contain *inter alia* particulars regarding the :—

- (a) industrial areas/estates and flatted factories complexes entrusted to the Corporation by the Government for development, operation and maintenance under the Act;
 - (b) Programme of work for the year under report;
 - (c) Progress of work during the year under the Act with particular reference to the
 - (i) land acquired,
 - (ii) development carried out,
 - (iii) amenities provided
 - (iv) industries established in the industrial areas/estates, and
 - (v) details of any other activities entrusted to and undertaken by the Corporation under and in accordance with the Act;
 - (d) Finance for Corporation, for activities under the Act;
 - (e) Establishment under the Corporation and Administration of its business for activities under the Act;
 - (f) Directions given by the Government to the Corporation under the Act and their compliance;
- (3) The Corporation shall also submit to the Government in April, July, October and January of each year, a progress report based on its working and accounts under the Act upto the end of the quarter immediately proceeding the months aforesaid.

CHAPTER-V

UNUTILIZED SURPLUS LANDS IN INDUSTRIAL AREAS

14. Acquisition of unutilized surplus lands in industrial areas and allotment to other industries under Section 15 of the Act.—Section 15(4) of the Act provides that upon the report submitted by the Corporation, the Government is satisfied that any plot holder has not utilized the minimum permissible buildable area as per building bye-laws of his plot during the maximum permissible period fixed by the Government from time to time from the date on which possession of

- 136/c
- (a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of sub-section (1); or
 - (b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed, is given or tendered to some person on the land or building or, where there is no person on the land or building to whom it can be delivered, is affixed to some conspicuous part of the land or building.
 - (3) Where a document is served on the firm in accordance with this section, the document shall be deemed to be served on each partner.
 - (4) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any property, the occupier (if any) of the property may be required by notice in writing by the Government or the Corporation, as the case may be, to state the name and address of the owner thereof

16. Filing of complaint under Section 28 of the Act.—An officer not below the rank of Deputy Commissioner of Industries in the Delhi Government and/or Executive Engineer in the Corporation shall be either generally or specifically authorized by the Corporation to file complaint of any offence relating to property belonging to, or vested by or under this Act in the Corporation, in the Court.

SCHEDULE-1

(See Rule - 8)

(in Rs.)

(1)	Total estimated expenditure to be incurred in providing amenities in the industrial area/ industrial estate/flatted factories complex	Ea
(2)	Total estimated receipts to be credited to the Industrial Development, Operation and Maintenance Fund under Section 8(1)(a), 8(1)(b), 8(1)(c), and 8(2) of the Act	Rf
(3)	Excess of expenditure over receipts	(Ea-Rf) ÷ Sf
(4)	Percentage of excess of expenditure over receipts to be recovered from the users (To be decided by the Corporation)	X%
(5)	Total Fee to be recovered from the users.	$\frac{X}{100} \times (Sf) \times M$
(6)	Total area of the plots in the industrial area/ industrial estate/flatted factories complex occupied by the users.	A Sq.mtr.
(7)	Share of fee/charges of each plot holder	$\frac{M}{A} \times \text{Area of plot/ flatted factory under possession of the plot holder}$

FORM 'A'

[See Rule 11(1) (2) (5)]

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

1. Budget estimates of the Corporation for the year

(REVENUE RECEIPTS)

(Rs. In thousands)

Sub-heads	Actuals for previous year	Budget Estimated for current year	Revised Estimates for the current year	Budget Estimates for next year	Remarks (Explanation for increase/decrease)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Subventions, grants, loans, advances or otherwise received from Government					

135/C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Fees				
3.	Ground Rent				
4.	Disposal of land, buildings and other properties movable and immovable				
5.	Annual rent of land leased				
6.	Annual rent of buildings				
7.	Service Charges				
8.	Conversion charges				
9.	Miscellaneous e.g. fines from contractors, forfeiture of deposits, interest				

Total: _____

Deficit: _____

(II) BUDGET ESTIMATES OF THE CORPORATION FOR THE

YEAR _____

(REVENUE EXPENDITURE)

(Rs. In thousands)

Sub-heads	Actual for previous year	Budget Estimated for current year	Revised Estimates for the current year	Budget Estimates	Remarks (Explanation for increase/decrease)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Administrative Expenses					
(a) Establishment and other charges					
(b) Contingencies					
Total I					
Deductper cent transferred to development expenditure in capital account.					
Net					
II. Executive Expenses---					
(a) Establishment and other charges.					
(b) Contingencies					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total II					
Deductper					
cent transferred to					
development					
expenditure in capital					
account.					
Ncl.					
III. Water supply and					
Electricity Supply					
Charges					
IV. Maintenance and					
repairs —					
Deduct ----- per cent					
transferred to					
development					
expenditure in capital					
account					
(V) Depreciation					
(VI) Expenditure in					
connection with issue					
of loans.					
(VII) Interest on					
loans					
(VIII) Sinking Fund					
Transfers					
(IX) Miscellaneous					
TOTAL:					
SURPLUS:					

(III) BUDGET ESTIMATE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR.....
(CAPITAL RECEIPTS)

Budget Head	Actual for previous year	Budget Estimated for current year	Revised Estimates for the current year	Budget Estimates for next year	(Rs. In thousands) Remarks (Explanation for increase/ decrease)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Loans received—					
(a) From Government					
(b) Owner loans (public or private)					
(2) Deposits—					
(a) For lease of plots and buildings					
(b) Other deposits					
(3) Miscellaneous					
(4) Sinking Fund transfers from Revenue					
Deduct—Investments					
TOTAL					
Capital Deficit					

(IV) BUDGET ESTIMATE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR.....

(CAPITAL EXPENDITURE)

(Rs. In thousands)

Budget Heads	Actual for previous year	Budget Estimated for current year	Revised Estimates for the current year	Budget Estimates	Remarks (Explanation for increase/ decrease)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(I) Fixed Assets					
(II) Development of					
(a) Industrial areas and Estates and Flatted Factories Complexes					
(b) Operation and Maintenance of Industrial Areas and Estates and Flatted Factories Complexes					
(III) Development of other Schemes.					
(IV) Development of Schemes undertaken for and on behalf of Government.					
Less deposits from Government.					
(V) Development of Schemes undertaken on behalf of bodies other than Government					
Less Deposits					
(VI) Stock					
(VII) Advances					
(VIII) Sundry Creditors (—)					
TOTAL					
Capital Surplus:					

(V) BUDGET ESTIMATE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR.....

(DETAILS OF SCHEME)

(Rs In thousands)

Name of Scheme	Total estimated cost	Expenditure up to 31st March 20.....	Actual is for previous year	Budget Estimates for current year	Revised Estimate for current year	Budget Estimates	Remarks (Explanation for increase/ decrease)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Survey and Planning							
2. Roads							
3. Water and waste water							
4. Storm water drains							
5. Electrical works							

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b) other loans cash or works expenditure					(iii) Technicians sheds. (iv) Flatted Factory Buildings Less receipts on Capital Account. 2. Water supply schemes expenditure		
B. Loans from public (separate heads to be opened for each issue)					Less Receipts on Capital account 3. Residential Buildings.		
C. Deposits received from Governments for scheme. undertaken for and on behalf of Government.					4. Other assets Less depreciation.		
D. Deposits for schemes entrusted by bodies other than Government.					5. Stock in hand		
E. Deposits— (1) For lease for plots and Buildings. (i) Developed parts of the state. (ii) Developing parts of the State					6. Cash		
(iii) Technicians sheds (iv) Flatted Factory buildings (2) For sheds in Functional Estate (3) For annual rent of land leased (4) Miscellaneous Deposits held on behalf of Government. (5) Other Deposits.					7. Remittance Inter-divisional adjustments. 8. Sinking Fund Investment Account (i) Investments (ii) Cash at Bank (iii) Accrued interest 9. Advances (a) Due from State Government (b) On account advance (c) Miscellaneous Advances. (d) Advances to Corporation employees		
F. Sundry creditors G. Sinking Fund H. Surplus							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Horticulture							
7. Buildings							
8. Miscellaneous including contingencies							
Total							
Revenue Surplus:			Revenue Deficit:				
Capital Surplus:			Capital Deficit:				
Explanatory Note:							

FORM "B"

[see Rule 11(1)(2)(5)]

ANNUAL PROGRAMME OF WORK

Serial No.	Name of Scheme	Estimated cost of the work	Estimated expenditure in the year for which programme is proposed	Estimated receipts	Salient features, amenities and facilities to Industries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FORM "C"

[see Rule 12(2)]

DELHI STATE INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

(i) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH -----

(Rs. In thousand)

At the end of	Liabilities	Total of detailed head	Total of sub-head	Total of major head	At the end of	Assets	Total of sub-head	Total of major head
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	A. Amount repayable to the Government Loans (a) Expenditure of B.I.D.					I. Industrial Areas and Estates:- (i) Developed parts of the State (ii) Developing parts of the State.		

Part IV]
 (iii) Statement showing expenditure on Development of Industrial Areas and Estate-Developed parts as on 31st March,

(Assets-Item 2)

(Rs. in thousands)

Up to 31st March,

Sl. No.	Name of the Scheme	Development Expenditure	Administrative Charges	Interest	Total Expenditure	Development Expenditure
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(Rs. in thousands)

Up to 31st March,

Administrative Charges	Interest	Total Expenditure	Development Expenditure	Administrative Charges	Interest	Development Expenditure
8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

iv) Schedule of other Assets as on 31st March

(Assets-Item 4)

Sl. No.	Name of Assets	Balance as on 31st March	Additions	Total as on 31st March	Disposals	Depreciation	Balance as on 31st March	Remarks
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

129/c

28

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

[PART

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(e) Amount recoverable.

10. Preliminary expenses in connection with issue of Loan Bonds-

(i) Discount on loan bonds

(ii) Other Expenditure deficit for.

(ii) Statement showing expenditure in Development of Industrial Areas and Estates

Developed parts as on 31st March,

Assets-Item I(i)

(Rs. in thousand)

Up to 31st March.....

Serial	Industrial	Development Expenditure	Administrative Charges	Total Expenditure
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(Rs. in thousands)

Up to 31st March.....

Development Expenditure	Administrative Charges	Total Expenditure	Development Expenditure	Administrative Charges	Total Expenditure
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March,.....

(Rs. in thou

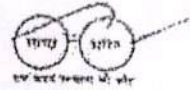
For Previous year	Expenditure	Total of Sub-Head	Total of Major-Head	For previous year	Income	Total of Sub-Head
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. Water Supply Schemes and Residential Building					
	(a) Water Supply :					
	(i) Establishment					
	(ii) Maintenance and Repairs					
	(iii) Royalty Charges					
	(iv) Interest					
	(b) Residential Buildings					
	(i) Establishment					
	(ii) Maintenance and Repairs					
	(iii) Interest					
	4. Maintenance and Repairs					
	Less : Recoveries on hiring of Tool and Plants					
	Less : 100 per cent transferred to Development Expenditure.....					
	5. Depreciation :—					
	(i) Executive					
	(ii) Administrative					
	Less-Transferred to Development Expenditure.....					
	6. Expenditure in connection with issue of loans					
	7. Interest on Loan :					
	Less :—					
	(i) Interest capitalized :					
	(a) Water Supply					
	(b) Residential buildings					
	(ii) Interest transferred to :					
	(1) Item 3 (a) above.....					
	(2) Item 3 (b) above.....					
	8. Miscellaneous					
	9. Amount transferred to sinking Fund					
	10. Surplus for the year.....					

By Order and in the
presence of the Lt. Governor of the National Capital Territory of
Delhi



NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER(ELECT.)
E-1 Block, 10th FLOOR, Dr.SPM CIVIC CENTRE
ILN MARG, NEW DELHI-110002

376424/11-1



No.CE(E)/NDMC/2021-22/ 437

Dated: 27/01/2022

To

The Chief Engineer(Electrical),
DSIIDC, Technical Centre Building,
Wazirpur Industrial Area,
Delhi-110052.

Sub: Regarding Handing Over of existing Streetlighting arrangement in Industrial areas under the jurisdiction of North DMC to the DSIIDC.

It is to state that in compliance of Pr.Secy(UD), Govt.of NCT of Delhi Orders No.13/65/2011/UD/MB/16873 dated 02.12.2012 and subsequent to the decision taken in the Meeting held on 20.01.2012 under the Chairmanship of Chief Secretary(GNCTD), duly conveyed vide letter No.EE(P&M)/321 dated 01.02.2012 regarding Transfer of Industrial Areas/Estates from Municipal Corporation of Delhi to Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation(DSIIDC), wherein the Competent Authority has approved transfer of the Industrial areas to DSIIDC, after inventorization of all the assets on the Lay Out Plan and requesting all the Chief Engineers to take immediate necessary action for getting the inventorization of all the assets on the LOP and thereafter transfer of said Industrial areas to DSIIDC. A copy of the same letter dated 01.02.2012 is attached herewith for information please.

In this regard, it is to mention that various complaints have been received with regard to non-availability of lighting in some of these Industrial areas resulting increase of theft etc. Since, North DMC was in the impression that the said sites have already been handed over and the responsibility of maintaining the streetlights rests with the DSIIDC whereas the DSIIDC was in the impression that the said sites have not been handed over till date, as such, both the agencies were not been able to maintain the streetlights in these areas.

The Inconvenience to the general public was discussed at the level of the Commissioner, North DMC and Managing Director, DSIIDC. To find way for resolution of the problem, it was decided to get a joint survey of these areas and prepare a plan/inventory for the same for notional Hand over/Taking over. Accordingly, the concerned Chief Engineer(Electrical) of the North DMC as well as Chief Engineer(Electrical) of the DSIIDC were directed to chalk out the plan for inventorization of all the assets of streetlights of these Industrial areas. In line with the same, Shri Sandeep Mittal, Executive Engineer(Electrical)/North DMC and Shri Mukesh Mann, Executive Engineer(Electrical)/DSIIDC, have been nominated as Nodal Officers from respective organization and they alongwith their team have been authorized to make joint survey of these sites and prepare a Handing over/Taking over report on the same. The Inventory of streetlights in these Industrial areas have been prepared jointly by these officers and the First lot of the said report have been prepared and attached herewith for information and further signature please.

Accordingly, as already settled, these need to be signed by both the authorities. Two copies of the said First lot report, jointly prepared, have been signed by the authorities of North DMC(Handing Over) is attached for signatures from your end i.e.DSIIDC(Taking Over) and necessary action in order to avoid Inconvenience of public at large.

This may please be accorded TOP PRIORITY.

Encl.: As Above.

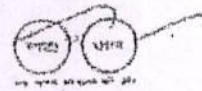
Kumar Santosh
Chief Engineer(Elect)
North Delhi Municipal Corporation





MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
OFFICE OF THE SUPDT. ENGINEER (ELECT.)
22nd FLOOR, Dr. SPM CIVIC CENTRE
JLN MARG, NEW DELHI-110002

36/0001-21



No. SL(8)1 No. 13/MS 9/2022/23

Dated: 20/12/2022

To
Copy
The Chief Engineer (Electrical),
DSIIDC, Technical Centre Building,
Wazirpur Industrial Area,
Delhi-110052.

Sub: Regarding Handing Over of existing Streetlighting arrangement in Industrial areas under the jurisdiction of North DMC to the DSIIDC.

It is to state that in compliance of Pr. Secy(UD), Govt. of NCT of Delhi Orders No 13/65/2011/UD/MB/16873 dated 02.12.2012 and subsequent to the decision taken in the Meeting held on 20.01.2012 under the Chairmanship of Chief Secretary(GMCTD), duly conveyed vide letter No.EC(PRM)/321 dated 01.02.2012 regarding Transfer of Industrial Areas/Estates from Municipal Corporation of Delhi to Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation(DSIIDC), wherein the Competent Authority has approved transfer of the Industrial areas to DSIIDC, after inventorization of all the assets on the Lay Out Plan and requesting all the Chief Engineers to take immediate necessary action for getting the inventorization of all the assets on the LOP and thereafter transfer of said Industrial areas to DSIIDC. A copy of the same letter dated 01.02.2012 is attached herewith for information please.

In this regard, it is to mention that various complaints have been received with regard to non-availability of lighting in some of these Industrial areas resulting increase of theft etc. Since, North DMC was in the impression that the said sites have already been handed over and the responsibility of maintaining the streetlights rests with the DSIIDC whereas the DSIIDC was in the impression that the said sites have not been handed over till date, as such, both the agencies were not been able to maintain the streetlights in these areas.

The inconvenience to the general public was discussed at the level of the Commissioner, erstwhile North DMC and Managing Director, DSIIDC. To find way for resolution of the problem, it was decided to get a joint survey of these areas and prepare a plan/inventory for the same for notional Hand over/Taking over. Accordingly, the concerned Chief Engineer(Electrical) of the North DMC as well as Chief Engineer(Electrical) of the DSIIDC were directed to chalk out the plan for inventorization of all the assets of streetlights of these Industrial areas. In line with the same, Shri Sandeep Mittal, Executive Engineer(Electrical)/erstwhile North DMC and Shri Mukesh Mann, Executive Engineer(Electrical)/DSIIDC, have been nominated as Nodal Officers from respective organization and they alongwith their team have been authorized to make joint survey of these sites and prepare a Handing over/Taking over report on the same. The inventory of streetlights in these Industrial areas were prepared jointly by these officers and the First lot of the said report was prepared and forwarded vide letter bearing No.CE(E)/NDMC/2021-22/427 dated 27.01.2022 for information and further signature at your end(copy enclosed). However, the same has not been finalized as yet.

Accordingly, it is again submitted that these need to be signed by both the authorities. Two copies of the said First lot report, jointly prepared, have been signed by the authorities of MCD(Handing Over) and is attached for signatures from your end i.e. DSIIDC(Taking Over) and necessary action in order to avoid inconvenience of public at large.

This may please be accorded **TOP PRIORITY**.

Encl.: As Above.

[Signature]
Supdt. Engineer (Elect.)-I
Municipal Corporation of Delhi
22nd Floor, Dr. SPM Civic Centre
JLN Marg, New Delhi-110002



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (ELECTRICAL)-I

Room No.1004, E-1 Block, 10th Floor, DR. SPM CIVIC CENTRE

J.L.N MARG, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002.

Tel. No.011-23226011

No.C.E (E)-I/MCD/2023/ 53

Dated: 23/01/2023

Sh. Vivek Behl
Chief Engineer (Elect.) / DSIIDC,
Technical Centre Building,
Wazirpur Industrial Area,
Delhi-110052

Sub:-Regarding pending payment of Electricity Bills for Street lights under the jurisdiction of MCD

Ref:- DSIIDC/CE/Elect./St.L/2022-23/68

Dated: 02/01/2023.

TPDDL/G&I/2022-23/1679

Dated: 21.11.2022.

This has reference to above, may please be recalled the orders from the Pr. Secy. (UD), Govt. of NCT of Delhi, orders no.13/65/2011/UD/MB/16873 dated: 02.12.2012 and decision taken in the meeting held on 20.01.2012 under the chairmanship of chief secretary (GNCTD), duly conveyed vide letter No.EE(P&M)/321 dated: 01.02.2012, regarding transfer of industrial areas/estates from Municipal Corporation of Delhi to Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC), wherein the competent authority has approved transfer of the industrial areas to DSIIDC, after inventorisation of all the assets on the lay out plan and directing all the Chief Engineers to take immediate necessary action for getting inventorisation of all the assets on the LOP and thereafter transfer of said industrial areas to DSIIDC.

Subsequently, the matter was discussed at the level of the Commissioner, erstwhile North DMC and Managing Director, DSIIDC and as decided in this discussion, a joint team was formed to survey of these areas and prepared a plan/inventory for the same for notional hand over/taking over. Accordingly, the inventory of streetlights in these industrial areas were prepared jointly by the team and the first lot of the said report was prepared and forwarded vide letter bearing no. C.E(E)/NDMC/2021-22/427 dated 27.01.2022 to DSIIDC for information and further signature at the end of DSIIDC (copy enclosed). However, the same has not been finalized / taken-over by the DSIIDC. Subsequently, a no. of letters from respective Electrical divisions were communicated to M/s DSIIDC for completion of handing-taking over formality and joint survey of remaining areas, in addition DSIIDC was also requested for payment to M/s TPDDL towards the electricity bills for streetlighting in various industrial areas under their jurisdiction, but neither any action nor replies have been received from DSIIDC in this regard. (Copies of the letters are enclosed for ready reference.

Now, in response to the FINAL DISCONNECTION NOTICE, served by M/s TPDDL to DSIIDC vide no. TPDDL/G&I/2022-23/1679 dated: 21.11.2022, for disconnection of electricity supply for such streetlighting connections. The Chief Engineer (Electrical), DSIIDC has submitted a reply to M/s TPDDL and copy of the same letter has been endorsed to the MCD (Copies enclosed).

In this letter, it seems that the DSIIDC is trying to transferring his responsibilities towards the MCD. Whereas, as per decisions taken in year - 2012-13 at appropriate level, all such streetlights in Industrial areas supposed to be jointly surveyed and taken-over by M/s DSIIDC for further, repair maintenance and payment of electricity charges etc.

The point-wise replies for the letter of DSIIDC, marked to the MCD are as under:-

1. The DSIIDC should take-over, the jointly surveyed streetlights in industrial areas at once and to expedite joint survey for remaining areas so as to earliest completion of handing / taking over of streetlighting and to own the responsibilities for repair, maintenance and payment of electricity charges for these streetlighting in industrial areas, in compliance to the order of the Pr. Sec (UD), Govt. of NCT of Delhi Orders No.13/65/2011/UD/MB/16873 dated: 02.12.2012, which has been communicated to M/s DSIIDC through various letters from Electrical divisions, MCD.

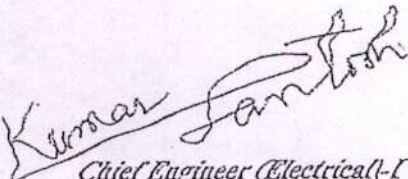
2. Because of no response from the DSIIDC for a no. of written communications from respective Electrical divisions and HQ, the MCD is forced to discontinue payment of electricity charges against streetlighting connections in DSIIDC areas. Regarding, electricity meters in the name of MCD, it might be possible that the developer had applied electricity meter in the name of MCD and the DSIIDC didn't changed nominations in electricity meters connection till dated. Hence, the DSIIDC should get the ownership of streetlights electricity meter changed in their name and must pay the Electricity Bills at earliest.
3. Further, in-line with the procedures being followed by the DSIIDC in Narela industrial area. The DSIIDC should own their responsibilities to pay electricity charges & Maintenance charges against public lighting in other industrial areas as well, as policies may not be differentiated for different areas in Delhi.

Hence, in order to maintain law & order in DSIIDC's industrial areas and to facilitate public at large, M/s DSIIDC to own their responsibilities and to pay for repair, maintenance and electricity bill payment etc. for streetlights in various industrial areas of DSIIDC.

Sd/-
Chief Engineer (Electrical)-I

Copy to:-

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. PS to Commissioner: - | } | For kind information of Commissioner. |
| 2. Addl. Commissioner (Engg.) | | |
| 3. Engineer-in-Chief - I | } | For kind information. |
| 4. S.E (Electrical)-II | | |
| 5. Office Copy | | |


Chief Engineer (Electrical)-I



MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
(Engineering Department)

OFFICE OF CHIEF ENGINEER (ELECT.)-I

Room No. 204, 2nd Floor, Dr. SPM Civic Centre, Minto Road, Delhi-110002

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

No. 86 /CE (Elect.)-I/2023-24

Dated: 20/12/2023 JT-4

Sh. Vivek Behl
Chief Engineer (Elect.) / DSIIDC,
Technical Centre Building,
Wazirpur Industrial Area,
Delhi-110052

Sub:- Regarding pending payment of Electricity Bills for Street lights under the jurisdiction of MCD

Ref:- Previous Communication in subjected matter as under:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. DSIIDC/CE/Elect./St.Lt/2022-23/68 | Dated: 02/01/2023. |
| 2. CE (Elect.)-I / MCD/ 2023/53 | Dated: 23.01.2023. |
| 3. TPDDL/G&1/2022-23/1679 | Dated: 21.11.2022. |

This has reference to above, may please be recalled the orders from the Pr. Secy. (UD), Govt. of NCT of Delhi, orders no. 13/65/2011/UD/MB/16873 dated: 02.12.2012 and decision taken in the meeting held on 20.01.2012 under the chairmanship of chief secretary (GNCTD), duly conveyed vide letter No.EE(P&M)/321 dated: 01.02.2012, regarding transfer of industrial areas/estates from Municipal Corporation of Delhi to Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC), wherein the competent authority has approved transfer of the industrial areas to DSIIDC, after inventorisation of all the assets on the lay out plan and directing all the Chief Engineers to take immediate necessary action for getting inventorisation of all the assets on the LOP and thereafter transfer of said industrial areas to DSIIDC.

Subsequently, the matter was discussed at the level of the Commissioner, erstwhile North DMC and Managing Director, DSIIDC and as decided in this discussion, a joint team was formed to survey of these areas and prepared a plan/inventory for the same for notional hand over/taking over. Accordingly, the inventory of streetlights in these industrial areas were prepared jointly by the team and the first lot of the said report was prepared and forwarded vide letter bearing no. CE(E)/NDMC/2021-22/427 dated 27.01.2022 to DSIIDC for information and further signature at the end of DSIIDC (copy enclosed). However, the same has not been finalized/taken-over by the DSIIDC. Subsequently, a no. of letters from respective Electrical divisions were communicated to M/s DSIIDC for completion of handing-taking over formality and joint survey of remaining areas, in addition DSIIDC was also requested for payment to M/s TPDDL towards the electricity bills for street lighting in various industrial areas under their jurisdiction, but neither any action nor replies have been received from DSIIDC in this regard. (Copies of the letters are enclosed for ready reference.

Due to non-receipt of payment towards energy and maintenance by TPDDL, a FINAL DISCONNECTION NOTICE, served by M/s TPDDL to DSIIDC vide no. TPDDL/G&1/2022-23/1679 dated: 21.11.2022, for disconnection of electricity supply for such street lighting connections. The Chief Engineer (Electrical), DSIIDC has submitted a reply to M/s TPDDL and copy of the same letter has been endorsed to the MCD.

In this letter, the DSIIDC is trying to transferring his responsibilities towards the MCD. Whereas, as per decisions taken in year 2012-13 at appropriate level, all such streetlights in Industrial areas supposed to be jointly surveyed and taken-over by M/s DSIIDC for further, repair maintenance and payment of electricity charges etc.

The point-wise replies for the letter of DSIIDC, marked to the MCD are as under:-

1. The DSIIDC should take-over, the jointly surveyed streetlights in industrial areas at once and to expedite joint survey for remaining areas so as to earliest completion of handing / taking over of street lighting and to own the responsibilities for repair, maintenance and payment of electricity charges for these street lighting in industrial areas, in compliance to

122/K

119/c

1. the ord (JD), Govt. of NCT of Delhi Orders No.13/65/2011/UD/MB/16873 dated: 02.12.2011, has been communicated to M/s DSIIDC through various letters from Electrical divisions, MCD.
2. Because of no response from the DSIIDC for a no. of written communications from respective Electrical divisions and HQ, the MCD is forced to discontinue payment of electricity charges against street lighting connections in DSIIDC areas. Regarding, electricity meters in the name of MCD, it might be possible that the developer had applied electricity meter in the name of MCD and the DSIIDC didn't changed nominations in electricity connection till dated. Hence, the DSIIDC should get the ownership of streetlights electricity changed in their name and must pay the Electricity Bills at earliest.
3. Further, in-line with the procedures being followed by the DSIIDC in Narela, Bawana, Bhorgarh etc industrial area. The DSIIDC should own their responsibilities to pay electricity charges & Maintenance charges against public lighting in other industrial areas as well, as policies may not be differentiated for different areas Delhi.

Hence, in order to maintain law & order in DSIIDC's industrial areas and to facilitate public at large, M/s DSIIDC to own their responsibilities and to pay for repair, maintenance and electricity bill payment etc. for streetlights in various industrial areas of DSIIDC.

sd-
Chief Engineer (Electrical)-I

Copy to:-

1. PS to Commissioner
2. Addl. Commr. (Engg.)
3. Engineer-In-Chief
4. Chief Engineer (Electrical)-I
5. Office Copy

AE 20/12
Chief Engineer (Electrical)-I



TATA POWER-DDL

158/c
Annexure - A

(23)

TPDDL/GA/2024/226

Office of Head of Group (Govt Affairs)
August 13, 2024

Mr. Rajesh Gupta
Hon'ble MLA
11/3A MIG Flats Pocket B
Ashok Vihar Phase - 3, Delhi - 110052

Subject: Shifting/ conversion of HVDS Network into LTABC network at Wazirpur J.J. Colony Constituency.

Dear Sir,

We write in reference to your letter on the above noted subject regarding Shifting/ conversion of HVDS Network into LTABC network at K, A and L Block Wazirpur J.J. Colony Constituency.

We wish to inform you that a joint site visit was carried out on dated 07.08.2024 at the above noted site along with your representative Mr. Dr. Asad Khan (+91- 9811503106) for above blocks only (K,A&L). During site visit it has been observed that Shifting/ conversion of HVDS Network into LTABC network is technically feasible.

In this regard, we wish to inform that tentative estimated cost for conversion from HVDS to LVDS for above 3 blocks shall be around Rs. 2 cores (approx..). However, final estimated amount is subject to ETC approval.

Also, as per requirement of UD deptt, NOC form LOA is required, which is DUSIB in this case, and for above locations a proposed sub-station is required to be installed. Same need to be communicated to DUSIB as existing sulabh complex need to dismantled as suggested by your representative during the visit for proposed Sub Station. A written consent from LOA is required for execution of the project. Also, for installation of new street light in the same area as requested by yourself was also explored, same can only be installed post conversion of HVDS Network to LVDS network for which a separate request letter will be required from your good office for utilizing MLALAD fund.

Site observations were also conveyed to your representative during the joint site visit. Site photographs are also enclosed for your kind reference. You are requested to kindly arrange the NoC from LoA and provide your consent for utilizing the MLALAD fund for above work so that estimate can be put up to upcoming ETC meetings, as & when scheduled.

This is for your kind information and perusal. We shall be pleased to furnish and other information/ clarification on the same as and when required.

Regards,

Shishir Taneja

Head of Group- Govt. Affairs

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
(A Tata Power and Delhi Government Joint Venture)

Regd. & Corp. Office : NDPL House Hudson Lines Kingsway Camp Delhi - 110 009
Website : www.tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526

Email : tpddl@tatapower-ddl.com Tel. : 011-6611 2272



TATA POWER-DDL

TPDDL/GA/2024/ 238

Office of Head of Group (Govt Affairs)
August 23, 2024Deputy Secretary (Power)
Department of Power, Govt. of NCT of Delhi
8th level, B- Wing, Delhi Secretariat
I.P. State, Delhi - 110002

Sub: Minutes of Meeting dated 30.07.2024.

Dear Sir,

In reference to your letter no. F/6/87/Power/2024/2563-2574 dated 30.07.2024 on the above noted subject regarding issues raised by Sh. Rajesh Gupta, Hon'ble MLA.

Please find below point wise response of Tata Power-DDL on the issues discussed during the meeting:

Sr. No.	MoM Point No.	Issues raised by Sh. Rajesh Gupta, Hon'ble MLA	ATR
1	4.1	Relocation/ shifting of DT in the Wazirpur Village.	Joint Site visit has been done along with MLA on 26.07.2024. an alternate space has been identified for shifting of the subject transformer, subject to NoC from the respective LoA. Case will be put-up in upcoming ETC meeting for approval as and when scheduled.
2	4.2	Issue related to load enhancement on annual basis	Load enhancement is being done as per the Regulations by the DERC time to time.
3	4.3	Issue related to tree trimming around the street lights in Ashok Vihar area.	The tree trimming has been done at the locations provided by Hon'ble MLA with the support of PWD Horticulture Department.
4	4.4	New connection issue at the drainage (Nala) under Wazirpur Constituency	Matter has been examined and site was also visited but no such connection has been found at the drainage (Nala) under the jurisdiction of Tata Power-DDL. It is requested to provide the specific details of the such connection, If any, so that matter can be examined specifically. However, connection are being granted to approved Theh-Bazarri's on the basis of allotment letter issued by respective LOA.

This is for your kind information please.

Regards,

Shishir Taneja
Head of Group- Govt. Affairs**TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED**
(A Tata Power and Delhi Government Joint Venture)Regd. & Corp. Office : NDPL House Hudson Lines Kingsway Camp Delhi - 110 009
Website : www.tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526
Email : tpddl@tatapower-ddl.com Tel. : 011-6611 2272